

नान का पुजा ५१

पुजी का शिक्षा

शिक्षा के स्वरूप तुकाने
के लिए 'हिंगो'
गिरवी रखने पड़ी

में उच्च शिक्षा
के लिए स्वरूप
नहीं
ले सकता

उच्च
शिक्षा अब
गोंदों के लिए नहीं

CL:5 PEA
2443

Class No.

Author

No. No. 2443

पीस एफ
नई दिल्ली

प्रकाशित



इस शिक्षा का अर्थशास्त्र

21/10/2015 पाण्डेय
2015-16

पिछले दिनों शिक्षा जगत में अबनी-बिडला द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट 'ए पांतिसी फ्रेमवर्क फॉर रिफार्म्स इन एजुकेशन' की चर्चा जोर-शोर से होती है। दरअसल यह रिपोर्ट कई अन्य चीजों के साथ-साथ उच्च शिक्षा में राज्य की भूमिका को समाप्त करने की सिफारिश करती है। यह सोच कल्याणकारी राष्ट्र की अवधारणा के प्रतिकूल है। इस पूरी चर्चा के संदर्भ में राष्ट्रीय सहात नामक अखबार ने अपने शानिवारीय परिशिष्ट 'हस्तक्षेप' में कई शिक्षाविदों और बुद्धजीवियों के लेख प्रकाशित किए। ये लेख रिपोर्ट के तमाम पहलुओं पर एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। आप तक इनको पहुंचाने के उद्देश्य से 'हस्तक्षेप' के कुछ लेखों को एक पुस्तिका के रूप में हम प्रकाशित कर रहे हैं।

मुकेश अबनी और कुमारमालम बिडला ने शिक्षा रिपोर्ट सन् 2015 के हिन्दुस्तान की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गयी है। यह मानकर चला गया है कि 2015 में देश की कुल आबादी करीब 1 अरब 25 करोड़ होगी। इसमें 5 से 24 वर्ष की आयु वालों की सङ्ख्या लगभग 45 करोड़ होगी। 5 से 19 वर्ष की आयु वाले सभी करीब 34 करोड़ लोगों के लिए कशा एक से बाहर तक की पढ़ाई अनिवार्य करनी होगी और बाकी 11 करोड़ में से कम से कम 2.2 लाख लोगों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। इन दोनों उद्योगपतियों का आकलन है कि 19 से 24 वर्ष आयु की कुल 11 करोड़ आबादी का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा यानी 2.2 करोड़ छात्र ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग्य होंगे। इनी बड़ी सङ्ख्या को शिक्षित करने के लिए सन् 2015 तक देश को अतिरिक्त करीब 7 लाख 32 हजार प्राथमिक स्कूल, 23 हजार 600 माध्यमिक स्कूल और उच्च शिक्षा के लागभग 27 हजार कॉलेज-विश्वविद्यालय खोलने पड़ेंगे। अभी हमारे पास इसके आधे या ताहाई स्कूल-कालेज ही हैं। यानी हमें दो से तीन गुना ज्यादा स्कूल-कालेज खोलने पड़ेंगे। एक प्राइमरी स्कूल और एक उच्च शिक्षा के कॉलेज या संस्थान के लिए यह रकम क्रमशः 20 लाख और 40 लाख रुपये पहुंचेगी। इस तरह कुल करीब 88900 करोड़ रुपये पूँजी व्यय का अनुमान लगाया गया है। चूंकि यह आने वाले 15 वर्षों का लक्ष्य है इसलिए 88900 करोड़ रुपये की राशि मुश्किल रख रही पड़ेंगी। इस पूँजी व्यय में करीब 5900 करोड़ रुपये की राशि मुश्किल रख रही पड़ेंगी। इस पूँजी व्यय में स्कूल-कालेज का भवन निर्माण, फर्नीचर, सचार उपकरण एवं कम्प्यूटर आदि को शामिल किया गया है। यह अनुमान 1998-99 की कीमतों पर है।

यह तो हुआ पूँजी व्यय। इसके अलावा इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2015 में शिक्षा का सावधि (तिकिंग) खर्च सालाना करीब 1 लाख 80000 करोड़ रुपये होगा। इसमें स्कूल-कालेजों के संस्थापन खर्च, नैनिट खर्च,

शामिल कर लिया जाय तो स्नातक की एफ् सामान्य डिग्री हासिल करने के लिए एक छात्र को प्रतिवर्ष कम से कम एक-हेड़ लाख रुपये खर्च करने हों। अगर कोई छात्र उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए 5-7 साल विश्वविद्यालय-कॉलेज में जुजारता है तो उसके पिता को सात-आठ लाख रुपये का इंतजाम करके चलना होगा। अगर वह इंजीनियरिंग, मैट्रिकल, और बीजेटेंट या अन्य व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली का उच्च लाख रुपये खर्च करना चाहता है तो उसे कम इससे पांच गुनी ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी। ध्यान रहे कि अंबानी-बिडला का यह आकलन 1998-99 की कामतों पर आधारित है। सन् 2015 में रुपये की कीमत क्या रहेगी, इसका आप अंदराजा लगा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 15 वर्षों में इसमें लगा भग तीन गुना की त्रुटि होगी और 35 हजार की जगह एक छात्र को बौतर फीस सालाना करीब एक लाख रुपये अदा करने पड़ेंगे। खाने-रहने और कॉम्पी-किताब का जो खर्च होगा वह अलग है।

अब प्रश्न यह है कि इतनी रकम देकर कैन पढ़ाई करेगा? वही जो करोड़पति पिता का पुत्र है। गरीब या मध्यवर्गीय परिवर्तों के लड़के उच्च शिक्षा से बच्चित हो जाएंगे। अंबानी-बिडला ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि सरकार चाहे तो गरीबों की शिक्षा के लिए ऋण देने का प्रावधान कर सकती है। अब भला सोचिए कि कौन पिता अपने बेटे को पढ़ाने के लिए 10-15 लाख रुपये का ऋण लेगा? अगर ऋण ले भी लिया तो उसे चुकाएगा कैसे? जिस लड़के को पढ़ाई के लिए वह इतनी रकम खर्च करेगा उसके रोजार की गांठी भी नहीं होगी। कर्ज में जमा और पला-बड़ा भारत का गरीब मध्यवर्गीय परिवार कर्ज में ही मर जाने को अभिशप्त होगा। यही है अंबानी-बिडला की शिक्षा की अर्थशाल्य की असलियत।

अध्यापकों का बेतन, पाठ्य-पुस्तकें एवं प्रशिक्षण सामग्री पर खर्च होने वाली धनराशि शामिल है। इस समय हमारे देश में करीब 50 लाख अध्यापक हैं लेकिन यह अनुमान भी 1998-99 की कीमतों पर ही अधारित है। सावधि खर्चों का पूँजी व्यय को मिला दिया जाय तो सन् 2015 से देश को शिक्षा पर प्रतिवर्ष तकरीबन 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

अंबानी-बिडला के मुलाकिव प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की केंद्रीय नियंत्रणदारी सरकार को लेनी चाहिए। जबकि उच्च शिक्षा को निजी क्षेत्र के हवाले कर देना चाहिए। इनके द्वारा दी गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले कुल व्यय का 90 प्रतिशत भाग सरकार को वहन करना होगा। माध्यमिक शिक्षा के खर्च का आधा सरकार और आधा निजी क्षेत्र वहन करेगा जबकि उच्च शिक्षा पर होने वाले कुल खर्च में अकेले निजी क्षेत्र का योद्दगान 63 प्रतिशत होगा। इस रिपोर्ट का सर्वाधिक जोर इस बात पर है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के खर्चों को तो सरकार समाज कल्याण के नाते उठा सकती है लेकिन उच्च शिक्षा पर व्यय होने वाली समृद्धी धनराशि की उगाही छात्रों और उनके अधिभावकों से ही होगी।

इस रिपोर्ट के मुलाकिव सन् 2015 से उच्च शिक्षा पर सालाना कुल करीब 42000 करोड़ खर्च होंगे। इसके अतिरिक्त आने वाले 15 वर्षों में भारत सरकार को नये उच्च शिक्षा संस्थानों के निर्माण में करीब 11 हजार करोड़ रुपये की पूँजी लगानी पड़ेगी। यानी प्रतिवर्ष उसे लगभग 732 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश करना होगा। चूंकि बाजार का अर्थशास्त्र इसकी इजाजत नहीं देता कि लगायी गयी पूँजी खर्च वाला आंकड़ा हर हाल में 75000 करोड़ रुपये पार कर जाएगा। चूंकि उस खर्च वाला अंकड़ा हर हाल में भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों की संख्या लगभग 2.2 करोड़ होगी, इस अर्थशास्त्र को स्वीकार कर लिया जाय तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लिहाजा यह पूरी धनराशि इन्हीं को अदा करनी होगी। यदि अंबानी और बिडला के इस अर्थशास्त्र को प्रतिवर्ष करीब 35 हजार रुपये बौतर फीस देने पड़ेंगे। ध्यान औसतन हर छात्र को प्रतिवर्ष करीब 35 हजार रुपये बौतर फीस देना जरूरतों पर रहे कि छात्रावास, खाना, कपड़ा-किताब और छात्र जीवन की दैनंदिन जरूरतों पर खर्च होने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं है। अब इसमें इन सारे खर्चों को भी

अंबानी-बिड़ला समिति की सिफारिशें

अखिलेश चुमन

- शैक्षिक कार्यक्रमों में प्राथमिक शिक्षा को सर्वान्व प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस लिहाज से प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए आवश्यक बनाया जाय तथा इसे मुफ्त किया जाय। माध्यमिक शिक्षा को भी 15 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए आवश्यक बनाया जाय।
- शिक्षकों के सतत प्रशिक्षण एवं जुगाड़ा विकास के लिए कारबून बनाया जाय।
- सूचना प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा सार्वजनिक लॉगों की स्थापना की जाय।
- शिक्षकों की भूमिका को प्रोत्साहक एवं डिप्टरेक के रूप में तब्दील किया जाय तथा बच्चों को अध्यास एवं अनुभवों के जरिये शिक्षित करने पर जरूर दिया जाय।
- माध्यमिक स्तर और उससे ऊपर के विद्यार्थियों को आवश्यक व्यावसायिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय।
- औपचारिक शिक्षा के विकल्प के रूप में इन्स्ट्रुमेंट शिक्षा को बढ़ावा दिया जाय।
- पूर्ण प्राथमिक शिक्षा में नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाय और प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में भी इसे मजबूती से लाए किया जाय।
- स्कूल स्तर पर समान शिक्षा पद्धति लाए को जाप लोकन उसमें क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर खासकर भाषा, इंटहस एवं सास्कृतिक विविधता की गुंजाइश रखी जाय।
- शिक्षा के प्रबन्धन को विक्रोक्त किया जाय। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रमों में वित्तीय एवं प्रबन्धन की जिम्मेदारी पांचायत स्तर पर हो।
- पेंगोग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सेट, जी.आर.ई. एवं जीमैट की तर्ज पर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाए। साथ ही एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानांतरण का आधार प्राप्तांक को बनाया जाय तथा इसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट (स्थानांतरण प्रमाण-पत्र) की आवश्यकता को खत्म किया जाय।

- शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम एवं सुविधाओं को बाजारोंनुखी बनाया जाय।
- सरकारी स्कूलों में भवन, टेलीफोन एवं कंप्यूटर के लिए प्राथमिकता के आधार पर गांशि मुहैया करायी जाय। इसके साथ विश्वविद्यालयों को दी जाने

प्रौद्योगिकी आवश्यक विश्व व्यवसाय में वृद्धि का आकलन
(अरब डॉलर में)

	वर्ष 2000	वर्ष 2010
सेत्र	70	160
एसोसिएशन	300	1,100
हवा वड्डांग	10	60
बियोमेट्रिक	450	880
मलाझुक्स शालगी	189	630
कम्प्यूटर उपकरण	843	1,300
इंटरनेट	785	2,300
साप्टवेर	270	630
इस्टचार चेवार	250	500
इस्टचार उपकरण	5	10
गोबोटिक्स एवं परोनोकरण	3,172	7,560
गुल	-	4388
स्त चर्चे में वृद्धि	-	36,600
विश्व भर का सकल घरेलू उत्पाद	30,000	
विश्व सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि (परिशेष ने)	11	21
विश्व व्यवसाय में हड्डी कुल	-	66%
वृद्धि में प्रौद्योगिकी का हिस्सा	-	
स्रोत : अंबानी-बिड़ला सिगेट, 2000		

- वाली वित्तीय सहायता कम की जाय तथा उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया जाय। इन संस्थानों के पाठ्यक्रम को भी सम्पादनकूल बनाया जाय।
- सरकार की भूमिका प्राथमिक शिक्षा को गांशि प्रदान कर उसे अनिवार्य तथा मुफ्त बनाने, माध्यमिक शिक्षा को गांशि प्रदान कर अनिवार्य बनाने, शत-प्रतिशत

इंसान को पंजी बनाने की साजिश

अनिल सद्गोपाल

- साक्षरता लाने, गैर बाजारोंमुखी शिक्षा की मदद करते, उने गये उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद करने व कोष प्रदान करने, छात्रों को कर्जे दिलाने भें वित्तीय गारंटी देने, पाठ्यक्रम तथा उसको गुणवत्ता में एकरूपता लाने तथा शैक्षक विकास योजना बनाने तक समिति किया जाय।
- कम सरकारी सहायता पाने या नहीं पाने वाले संस्थानों का संचालन तथा पाठ्यक्रम चयन में कल्पनाशीलता की स्वतंत्रता दी जाय।
- विज्ञान, तकनीकी, प्रबंधन तथा वित्तीय क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए नये नियोगिविद्यालय खोलने के लिए निजी विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया जाय।
- वित्तीय उपक्रमों में स्तर निर्धारण के लिए स्टैंडर्ड एंड पूर्कर्स या क्राइस्टल ऐसो संस्थाओं की तरह स्कूल, कालेजों, विश्वविद्यालयों या संस्थानों के स्तर को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा समय-समय पर उनकी भौतिकीय और उनका स्तर तय किया जाय।
- शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाय। शुरू में इसे विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा तक समिति किया जाय।
- प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता के लिए शिक्षा विकास कोष की स्थापना की जाय। इस कोष में हिये गये धन कां आयकर से मुक्त किया जाय।
- विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाय। शुरू में हमारे अंतर्राष्ट्रीय खाति वाले संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाय।
- सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच इस बात की सहमति बनायी जाय कि वे विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों से दूर रहें। विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा संस्थानों में राजनीतिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगायी जाय।
- अर्थव्यवस्था को नियंत्रण मुक्त किया जाय ताकि शिक्षा के लिए बाजार का विकास हो सके।
- स्नातक स्तर और उससे ऊपर हर क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित किया जाय।
- शिक्षकों के विकास के लिए सभी प्रशिक्षित शिक्षकों को एक निश्चित समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का प्रवधान किया जाय।
- कामगार तथा वर्चित वर्चों के वैकल्पिक शिक्षा देने के लिए विविध कार्यक्रम चलाये जाएं।

“अनिवार्य एवं नि-शूलक प्राथमिक शिक्षा को हमारे शैक्षिक एजेंडा में शीर्षस्थ स्थान दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद-45 में इनिट 14 वर्ष की आठ तक अनिवार्य शिक्षा के प्रति संवेधानिय काटिबद्धता को सर्वान्वय निर्णय ने यह कहकर गुट किया है कि शिक्षा एक के लिए सरकारी जन-विरोधी शिक्षा नीतियों के विरुद्ध संघर्ष का एलान कर रहा है। लेकिन अचारज तब होता है जब ये विचार भारत के दो बड़े पूँजीपतियों सर्वश्री मुकेश अंबानी एवं कुमारमंगलम बिडला व्यक्त करते हैं। इहाँने प्रधानमंत्री वाजपेयी के सामने अप्रैल 2000 में प्रस्तुत अपनी रपट में यह विचार व्यक्त किये हैं। ये दोनों पूँजीपति व्यापार एवं उद्योग पर गठित प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद के तहत शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश की नीति की रूपरेखा बनाने वाले विशिष्ट समूह के सदस्य हैं। उक्त रपट उन्होंने प्रधानमंत्री परिषद के सदस्य की हैसियत से दी है। आगे चलकर यह एप्ट बाजार-उन्मुख शिक्षा की विकालत करते हुए कहती है कि सरकार बड़ते क्रम में विश्वविद्यालयों को वित्तीय समर्थन देने में कटौती करती जाय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका अनुदान देने की नहीं रहनी चाहिए। सिकाय ऐसे क्षेत्रों के जिन्हें बाजार समर्थन नहीं देगा – गस्तर, भारीय भाषाएं, युत्तरवशाल, धर्म व दर्शनशास्त्र। कुल मिलकर रपट का कहना है कि प्राथमिक शिक्षा पर सरकार की भूमिका अधिकतम होनी चाहिए और उच्च शिक्षा परन्तु नहीं। इसी लार्किं क्रम में रपट में नये निजी विश्वविद्यालय खोले जाने हेतु एक निजी विश्वविद्यालय विधेयक बनाने की सिफारिश की गयी है। ऐसे विश्वविद्यालयों की खर्ची फैस का भार उठाने के लिए रपट विद्यार्थियों को कर्ज देने के प्रावधान करने और एक कर्ज उगाने वाली एजेंसी खड़ा करने

का भी सुझाव देती है। इस तरह एक ओर स्कूली शिक्षा के संदर्भ में समानांगक निर्जीकरण की मांग करती है। अब सचाल उठता है कि इन दोनों परस्पर विरोधाभासी स्वरों के बीच क्या कोई ताकिंक कड़ी है? यदि है तो क्या उस कड़ी को पहचाना जा सकता है?

इस रपट का स्पष्ट मानना है कि शिक्षा को सामाजिक विकास के एक आंकों के रूप में देखने का वर्तमान सोच हमें छोड़ना पड़ेगा। इसकी जाह हमें शिक्षा को एक ऐसे निवेश के रूप में देखना चाहिए जिसके सहारे एक नये सूचना-आधारित वैश्वीकृत समाज की रचना करना सभंव होगा। इसीलिए शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च सामाजिक खर्च न होकर, भारत के भविष्य-निर्माण में निवेश होगा। यह रपट की बुनियादी मान्यता है। समस्या इसी मान्यता से शुरू हो जाती है। इस सोच के तहत शिक्षा की साथकृता मानवीय और सामाजिक विकास के संदर्भ में नहीं देखी जाएगी, बरन् इससे होने वाले आर्थिक लाभों और इसके बाजार पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में आंकी जाएगी। यहाँ हमें मैकले को याद कर लेना चाहिए जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों के संदर्भ में शैक्षिक उद्देश्यों को ढाला था। आज यह रपट ठीक इसी सोच के तहत वैश्वीकरण क बाजारीकरण के संदर्भ में शिक्षा को ढालने पर जोर दे रही है। इसी मैकलेवाली बढ़ाई जा सकती है, प्रजनन रतों को घटाया जा सकता है और गरीब लोगों को ऐसे कोशल दिये जा सकते हैं जिनके सहारे वे अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी कर सकेंगे।

पूरा नजरिया अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है। ज्ञान की परिभाषा भी इसी संदर्भ में है। यानी, वही ज्ञान सार्थक है जो बाजार के वैश्वीकरण में मदद करता है। इस सोच के तहत ज्ञान का सीधा रिस्ता विश्व पूँजी निर्माण के साथ जोड़ा जाता है। ज्ञान ऐसा हो जो बाजार के पक्ष में अनुशासित, प्रशिक्षित, उत्पादक और सस्ता श्रमिक वर्ग तैयार करे और यह श्रमिक वर्ग गर्जनीकी रूप से स्थिर व्यापारिक माहौल बनाकर रखे। रपट के अनुसार इसानी पूँजी के निर्माण में ज्ञान का यह केवल एक पक्ष हुआ जो यह सुनिश्चित करेगा कि आम आदमी वैश्वीकरण के तहत विक रही नयी तकनीक को स्वीकारता जाय और उसमें

उत्पादक योगदान भी दे। इसके लिए स्कूली शिक्षा जरूरी है। इसानी पूँजी के निर्माण में ज्ञान की दूसरी भूमिका ऐसा इसान बनाने में होगी जो नयी तकनीकों के सूजन में योगदान दे। जिस अर्थव्यवस्था में नयी तकनीकों का सूजन होगा, वही अर्थव्यवस्था विश्व का नेतृत्व करेगी। अतः ऐसे इसान बनाना भी शिक्षा का काम होगा। यह शिक्षा चुनिंदा लोगों के लिए होगी जो विश्वविद्यालयों में दी जाएगी।

भारतीय सांविधान को लागू हुए पचास वर्ष हो गये और देश के आधं बच्चे (दो-तिहाई लड़कियां) स्कूली शिक्षा से बचत हैं। लंकिन कभी भी राजसत्ता और पूँजीपति वर्ग ने इन बच्चों के पक्ष में देश की प्राथमिकता बदलने और अनुच्छेद-45 को लागू करने की बकालत नहीं की। अब अचानक क्या हुआ है कि विश्व बैंक और यूरोपीय आर्थिक समुदाय से लेकर भारतीय पूँजीपति

रपट का दूसरा आवाय अधिकात्म एवं मध्यम वर्ग (खासकर अपरी मध्यम वर्ग) की शिक्षा से जुड़ा है। इस तबके के लिए उद्या युगवन्ता वाली उच्च शिक्षा का प्रावधान है। यह उच्च शिक्षा ऐसी इंसानी पूँजी का निर्माण करेगी जो सूचना ग्रीव्योगिकी हेतु निरंतर शोध करेगी और नये ज्ञान का सूजन करते हुए नये पूँजी निर्माण में योगदान देगी।

यह संभव करने के लिए रपट ने उच्च शिक्षा के निजीकरण का सुझाव दिया है। रपट उच्च शिक्षा के लिए एक नया सिद्धांत प्रतियादित करती है कि जो इस शिक्षा का उपयोग करे वह इसकी कीमत भी चुकाये। स्कूली शिक्षा के संदर्भ में यह सिद्धांत प्रत्यावित नहीं किया गया।

वर्ग-सभी को गरीब बच्चों को प्राथमिक (कक्षा 1-5) और उत्तर प्राथमिक (कक्षा 6-8) शिक्षा सुलभ करने का महत्व दिखने हो गा है? इस सवाल का उत्तर वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में न्यूनतम शैक्षिक स्तर बाल श्रमिक वर्ग की भूमिका से जुड़ा हुआ है। अब इन सभी ताकनों को समझा में आ गया है कि यदि श्रमिक वर्ग को न्यूनतम स्कूली शिक्षा नहीं मिली तो सूचना प्रेयोगिकी और अन्य नयी तकनीकों को फैलाने का काम रुक जाएगा और वैश्वीकरण व बाजारीकरण की रस्तार धीमी पद्ध जाएगी। अतः इस रपट में जोरदार पैरवी की गयी है कि

पा सकेंगे। लेकिन केवल 11.3 करोड़ कक्षा दस या बाहरी तक की शिक्षा पा सकेंगे। और उच्च शिक्षा केवल 2.2 करोड़ यानी देश के मात्र 6 प्रतिशत बच्चों को मिल पाएगी। ये 6 प्रतिशत बच्चे भी कहाँ वैश्वीकरण और विश्व बाजार के दर्शन पर सबाल छढ़े करना शुरू न कर दें इसलिए रपट बतौर साधारणी सुझाव देती है कि विश्वविद्यालयों में राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विदेशी शीघ्र लाया जाय। रपट की यह विडम्बना है कि इसमें एक और सूचना प्रैद्योगिकी हेतु ज्ञान-सूजन की क्षमता पैदा करने के लिए मुक्त चिंतन, शोध, स्वयं सीखना आदि गुणों वाली शिक्षा की वकालत की गयी है। लेकिन दूसरी ओर यही गुण सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ में वैश्वीकरण के लिए खतरनाक बन सकता है, यह भी माना गया है।

यदि अंबानी-बिडला की यह रपट स्वीकार ली जाती है तो भारत की भावी शिक्षा का रूप स्पष्ट हो जाता है। सन् 2015 में देश के श्रमिक वर्ग के बच्चे (लगभग 63 प्रतिशत) कक्षा आठ तक ही शिक्षित हो पाएंगे और इनके पास मात्र साक्षरता का कौशल होगा। ये गरीब बच्चे वैश्वीकरण द्वारा पैदा की गयी सूचना प्रैद्योगिकी व अन्य तकनीक का उपयोग करने वाले वैश्वीकृत श्रमिक बनेंगे। इन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां खरीद कर, एक देश से दूसरे देश ले जाकर अपने कारखानों में जोत सकेंगी-ठीक उसी प्रकार जैसे 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप और अमेरिका ने अफ्रीकी और एशियाई मजदूरों को गुलाम बनाकर खरीदा था। लागभग 31 प्रतिशत बच्चे जो मध्यम वर्ग के होंगे दसवीं या बारहवीं तक पढ़कर वैश्वीकृत बाजार में तकनीशियन बनेंगे और देश के मात्र 6 प्रतिशत बच्चे उच्च शिक्षा पाएंगे। वे ही नयी प्रौद्योगिकी का सूजन करेंगे और वैश्वीकरण बाजार में इस इसानी पूँजी की कीमत बढ़-चढ़कर लगायी जाएगी। अंततः वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था पर विश्व पूँजी की मालिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व बरकरार खड़ने में यह शिक्षा व्यवस्था मददगार होगी। तो यह है अंबानी-बिडली द्वारा प्रस्तावित शिक्षा व्यवस्था में छिपे वैश्वीकरण नव ग्राहमणवाद और नव मैकालेवाद का स्वरूप और यही है इसका लब्बेतुवाब।

रपट का दूसरा आयाम अभिजात्य एवं मध्यम वर्ग (खासकर ऊपरी मध्यम वर्ग) की शिक्षा से जुड़ा है। इस तबके के लिए उम्मा गुणवत्ता बाली उच्च शिक्षा का प्रावधान है। यह उच्च शिक्षा ऐसी इंसानी पूँजी का निर्माण करेगी जो सूचना प्रैद्योगिकों हेतु निरंतर शोध करेगी और नवे ज्ञान का सृजन करते हुए नये पूँजी निर्माण में योगदान देगी। यह संभव करने के लिए रपट ने उच्च शिक्षा के निजीकरण का सुझाव दिया है। रपट उच्च शिक्षा के लिए एक नया सिद्धांत प्रतिपादित करती है कि जो इस शिक्षा का उपयोग करे वह इसकी कीमत भी चाकायें। स्कूली शिक्षा के संदर्भ में यह सिद्धांत प्रस्तावित नहीं किया गया। निजीकरण से उच्च शिक्षा आम आदमी को पहुंच के बाहर हो जाएगी जो खर्चीली फीस का भार उठाने में सक्षम होंगे। उन्हें ही यह शिक्षा मिलेगी। लेकिन रपट लिखने वालों को यह चिंता भी है कि कुशाय बुद्धि वाले गरीब बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह गये तो उनका लाभ पूँजी निर्माण में नहीं निल पाएगा। अतः रपट का सुझाव है कि सरकार इन बच्चों को उच्चित शिक्षा हेतु कर्ज व छात्रवृत्ति देने का विराट प्रावधान बढ़ा करे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भी उच्च शिक्षा मंत्रालयों में प्रवेश के लिए अधिकृत भारतीय स्तर पर प्रवेश परीक्षण हो। इस सुझाव का मकसद पिछड़े तबके (दरिलत, अदिवासी, अन्य-संख्यक) के लोगों को उच्च शिक्षा से वंचित रखना है। इसका यह भी परिणाम होगा कि देश के पिछड़े क्षेत्रों के मध्यमवर्ग बच्चों के लिए भी उच्च शिक्षा पहुंच के बाहर हो जाएगी। ठीक यहाँ सुझाव हाल में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा जारी किये गये पाठ्यक्रम की रूपरेखा वाले दस्तावेज में भी है जिसमें एक गण्डीय परीक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

रपट में छिपा हुआ एंडेंडा उसको भावी योजना से स्पष्ट हो जाता है। सन् 2015 में एमी व्यवस्था होगी कि 22.6 करोड़ बच्चे कक्षा आठ तक की शिक्षा

उद्योगपतियों और राजनेताओं का

गठजोड़

प्रे. योगेन्द्र सिंह

उच्च शिक्षा में सरकारी भागीदारी की कम किये जाने के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि इससे शिक्षा का स्तर और उपयोगिता में बढ़ोत्तरी होगी। निजीकरण की वकालत करने वाली यह मानसिकता खुद में काफी सरिलिप्त है। निजीकरण किन स्थितियों में उत्पन्न होता है, पहले इसको समझने की कोशिश की जाय। ऐसा तीन वजहों से होता है। सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन न हो, सरकार की प्राथमिकता बदल रही हो या पुरानी पद्धतियों से होते आ रहे शोध की प्रक्रिया में कुछ ऐसी कमियां परिलक्षित हुई हैं जिन्हें निजीकरण के द्वारा दूर किया जा सकता है। यहां सबाल यह खड़ा होता है कि क्या वास्तव में उपरोक्त तीनों तत्व काम कर रहे हैं। अब तक तो सरकार उच्च शिक्षा पर कुल आव का छह फीसदी खर्च करने की अपनी वचनबद्धता ही नहीं निभा पायी है। तो क्या सङ्कट बनाने की तरह सरकार इस क्षेत्र में भी ऐसा न लगाने के बहाने खोज रही है? दूसरे, उच्च शिक्षा में सरकारी निवेश की कटौती करके क्या उसका उपयोग प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न आवामों को पूरा कर सकने में समर्थ हो? यदि ऐसा नहीं है तो इस निजीकरण के पीछे असली मंशा क्या है? अब तक हमारे यहां अलग-अलग क्षेत्रों में छोटे-बड़े जिन शोध हुए हैं वे सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा ही हुए हैं। कृषि में हरित क्रांति से लेकर रक्षा संकायों की आधुनिकातम तकनीकी तक कई सफलताओं का श्रेय इन्हें ही जाएगा। तो जहां-जहां इनसे चूक हुई है, क्या निजीकरण वास्तव में उन्हें दूर कर पाएगा? सीमित और तात्कालिक लाभ प्राप्त करने की मंशा शिक्षा को कोई नयी प्रसंगिकता प्रदान करेगी, इसमें सदैह है। क्या तब उच्च शिक्षा में पहले ही से चंचित गरीबों का प्रवेश लगाभगा असंभव नहीं हो जाएगा?

ऐसे में निजीकरण की सुगुणाहार के पीछे वास्तविक कारण क्या हो सकते

है? मेरे विचार में इसका असली कारण नयी मानसिकता, नया वर्ग-संतुलन, उद्योगपतियों और राजनेताओं का गठजोड़ है। आज तक हमारे उद्योगपतियों ने एवं किसी भी क्षेत्र में पैसा नहीं लगाया जहां मुनाफा न के बराबर हो। मुनाफाएँ और बाजार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या इस कथित उत्साह के पीछे वास्तविक तत्व मुनाफाखोरी नहीं है? पूरे विश्व में आज बाजार उत्पादन-प्रक्रिया की बजाय सेवा-विस्तार में फैल रहा है। कुल नियर्यात का 90 प्रतिशत गंभीर तत्व में होता है। उत्पादों का नियर्यात मात्र 10 फीसदी है। अर्थव्यवस्था के भूमिकालीकरण होने से अविकास या अद्विकास अब एक बाज़ न रहकर अवधार बन गया है। उसमें बाजार दूँड़ा जा रहा है। 'ग्रोथ विद्युत इमलायमंट' (रोजगार चिना वृद्धि) की अवधारणा तेजी से फैल रही है। थोड़े से लोग उच्च तकनीक द्वारा हीरे सारा उत्पादन कर रहे हैं। विकसित देशों में जनसंख्या नियन्त्रण से बढ़ों की तादाद बढ़ रही है। सेवानिवृत्ति की नीतियां बदल रही हैं। वहां 'मैन पावर' की समर्था हो एसे में उनका निशाना भारत है जहां पढ़ा-लिखा अंग्रेजों बोलने वाला सस्ता विद्युत प्रम है। यह बात भारतीय उद्योगपतियों की समझ में भी आने लगी है। जाने क्यों अब उन्हें भारत को 'नॉलेज सोसायटी' बनाने की फिफ्र बढ़ने लगी है। इन्हें नहीं मालूम कि सामाजिक प्रक्रियाएं किसी एक को इच्छा या किसी एक पार्टी से निर्धारित नहीं होती। यह ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा होती है जिनमें जनशक्ति और जनभार शामिल होते हैं। अभी तो भारत को अपनी वृनियादी भूमतों ही मजबूत करनी है। बौद्धिक कौशल को सब लोगों तक पहुंचाना है। गरीबी क्या से नीचे रह रहे 40 फीसदी लोगों तक शिक्षा-आरक्षण और कल्याणकारी दूसरी नीतियों का कोई लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा। वर्तमान स्थिति यह है कि 30 प्रतिशत मध्यवर्ग 100 फीसदी उच्च शिक्षा का पूरा लाभ गटक रहा है।

तकनीकी ने उत्पादन-प्रक्रिया को जिस तरह बदला है उसमें उत्पाद-निर्गम में लोगों की जरूरत काफी कम ही गयी है। दूसरी तरफ फलते-फूलते मध्यवर्ग की बढ़ती क्रयशक्ति और बाजार के अंधाधुंध विस्तार ने सेवा क्षेत्रों में नये-नये अवसर पैदा किये हैं। इनमें उच्च-शिक्षा भी प्रमुख अवसर है। पैसा लगान और बनाने के लिए बाजार की प्रसंगिकता शिक्षा में बढ़ने लगी है। इसलिए निजीकरण की जात हो रही है। बाजार का सर्व ही चुका है। 30 करोड़ का मध्यवर्ग और उसमें भी ऊपर का 8-10 करोड़ बाला उच्च मध्यवर्ग इसके लिए तेगार नैठा है।

नयी दास प्रवृत्ति का सूत्रपात

अनिल चौधरी

पर्यावरण के अधिक स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर बेइंतहा पैसा खर्च करने वाला यह तबका अपने बच्चों को उच्च शिक्षा भी खर्चते और विशिष्ट संस्थानों-कॉलेजों में दिलाना चाहता है। उसके लिए पांच सितारा 'अपोलो' जैसे संस्थान बनने ही चाहिए।

अमरीका और यूरोप में 90 प्रतिशत लोग हायर सेकेंडरी के बाद नौकरियां शुरू कर देते हैं। उच्च शिक्षा में बच्चे जाते हैं जो बाजारों-मुख नहीं हैं या जो बाजार में रहकर कपनियों के लाभार्थ शोध करते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता एक भौतिकविद् ने एक बार यह चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि अनुशृत शोधों (आद्यायड रिसर्चस) की तुलना में तात्त्विक शोधों (फँडामेंटल रिसर्चस) का प्रचलन आजकल काफी कम हो रहा है। उच्च शिक्षा के निजीकरण से शोध के क्षेत्र में यह असुलन हमारे यहां भी बढ़ सकता है। समष्ट है कि निजी संस्थाएँ या कर्म उद्दीपनी कामों में पैसा निवेश करेंगी जहां उन्हें तात्कालिक कामदा दिखेगा। यह हमारी शैक्षणिक व्यवस्था में बाजार द्वारा उत्पन्न एक विचलन होगा। भारत की संरचनात्मक प्रक्रिया जैसी है और उसमें राष्ट्रीय संकल्पना और जनमानस की आकांक्षा जिस तरह जुड़ी है, उस जनतानिक व्यवस्था में यह अपेक्षा करना कि नयी प्रक्रिया अगर कोई आधार पहुंचाती है, तो बहुमत्वक जनता उसे स्वीकार कर लेगी, गलत है। कई राजनीतिक दल तो इस सवाल को उठाने भी लगे हैं। जाहिर है कि गणतंत्रीय व्यवस्था के विकास में आंदोलन और दबाव की प्रक्रिया का यथेष्ट महत्व है। कोई भी नीति निर्धारित करने से पहले उसे समझता और सारे सदमों में देखना पड़ेगा। ऐसे में निजीकरण की प्रक्रिया सरकार की पूरक बनकर आती है और उसके अधुरे व अब तक अनेक पहलुओं पर काम करती है तब तो उसका कोई औचित्व भी है। इसके लिए पहले उसे अपना सामाजिक स्वरूप समष्ट करना होगा और स्वयं में एक कल्याणकारी भावना विकसित करनी होगी। क्या ऐसा संभव है?

प्रधानमंत्री को प्रस्तुत उद्योग और व्यापार परिषद की रिपोर्ट के निहितार्थ को समेजने के लिए दो व्यापक बिन्दुओं पर गौर फरमान बहुत जरूरी है। आज की बाजारों-मुखी व्यवस्था उन स्रोतों की खोज में है, जिनसे कि 'मुनाफे' को 'अक्षय' ('स्स्टेन्चिल') बनाया जा सके। यह व्यवस्था अच्छी तरह समझ चुकी है कि कार, फ्रिज, टीवी और वाशिंग मशीन अथवा साबुन, डिटरजेंट, टी वी कार्यक्रमों व चैनलों के जरिये 'मुनाफाखोरी' को अक्षय बनाना संभव नहीं है। न ही सड़कों, पुलों, बिजली संयंत्रों आदि ढांचागत उद्योगों से ऐसा कर पाना संभव है। उत्तराद्दन त्रांचागत दोनों ही प्रकार के उद्योगों की अपनी सीमाएँ हैं। इन दोनों से ही एक सीमा से अधिक 'मुनाफा' नहीं निचोड़ा जा सकता। अतः बाजारी ताकतों के लिए जरूरी है कि वे मानव जीवन की उन मौलिक आवश्यकताओं को मुनाफाखोरी का निशाना बनायें, जैसे कि खाद्यान, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। मुनाफाखोरों की इस मुहिम का मार्ग 80 के दशक में अमरीकी गद्दृपति रिगन और बरतानवी नायिका थैरर ने प्रशस्त कर दिया था। अब्बों डालर के खाद्यान बाजार पर चंद कंपनियों का एकाधिकार स्थापित हुआ। इसके बाद सामाजिक क्षेत्र के अंदर मुनाफाखोरों की संधें लगाने में संयुक्त राष्ट्र संस्थान व विश्व बैंक आदि 200 अब्ब डालर के शिक्षा बाजार व 80 अब्ब डालर के पानी के बाजार में निजी पूँजी अनेक रास्तों पर उत्पन्न हो रही हैं। जैसे-जैसे यूरेक्टों की परिक्रमा 'द कूरीयर' के नवबन्धर 2000 अंक में शिक्षा के विश्व बाजार का अनुमान 200 अब्ब डॉलर लगाया गया है और पत्रिका की सुखियों में अंक के पृष्ठ 18 पर 'कारपोरेट एनिल्सन' शीर्षक लेख का कहना है "जैसे-जैसे उदारीकरण की हड्डी जो पकड़ती जा रही है, शिक्षा जगत में एक ऐसी शब्दवाली जड़ जमाती जा रही है जो सीधे व्यापार जगत से उठायी गयी है। प्रधानमंत्रापक प्रबंधक को शूमिका अखिलायर करते जा रहे हैं तो अधिभावक नकचड़े ग्राहक की और स्कूल प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने की प्रतिस्पर्धा में यूं लिप्त है,

जिससे मुनाफा भी हो रहा है और बाज़र के लिए उपयुक्त स्नातक भी पैदा हो रहे हैं।"

इसी लेख में लेखिका सिंधिया गुरमन विश्व बैंक के हैरी पेटरसन को उद्देश्य करती हैं जो कहती हैं - "अभिभावक की अच्छी और अलग दिखने वाली शिक्षा की मांग ही इस क्षेत्र में निजी उद्यम को बढ़ावा दे रही है। अब अपेक्षाकृत गरीब देशों में भी लोग अपेंजी और तकनीकी शिक्षा की मांग कर रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि यह दोनों शारकत हैं औं: कुछ देश इन दोनों का भरपूर कामदा उठा रहे हैं। वे आश्वस्त हैं कि निजी शिक्षा अपने उम्रक्रम को उनकी अपेक्षाओं के उन्नेस्को की पविका 'द कूरियर' के नवम्बर 2000 अंक में शिक्षा व विश्व बाजार का अनुमान 200 अब डॉलर लगाया गया है और पविका की सुर्खियों में शिक्षा को मुनाफाखोरी के अन्तिम 'पड़व के लिये में प्रस्तुत किया गया है।

इस अंक के पृष्ठ 18 पर 'कारपोरेट एम्बेशन' शीर्षक लेख का कहना है - "जैसे-जैसे उदारीकरण की हवा जोर पकड़ती जा रही है, शिक्षा जगत में एक ऐसी शब्दावली जड़ जमाती जा रही है जो सोधे व्यापार जगत से उत्थायी गयी है। अखियार करते जा रहे हैं तो अभिभावक नक्ष्याएं ग्राहक की ओर स्कूल ग्राहकी व गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने की प्रतिस्पद्धा में यूं लिप्त हैं, जिससे मुनाफा भी हो रहा है और बाज़र के लिए उपयुक्त स्नातक भी पैदा हो रहे हैं।"

अनलूप ढाल सकता है।"

इस अंक में दिये गये तथ्य व आंकड़े बताते हैं

(पृ. 20) कि सन् 1980 में उच्च शिक्षा स्तर पर छात्रों की संख्या 5 करोड़ 20 लाख थी, जिसकी तुलना में सन् 1997 में यह संख्या बढ़कर 8 करोड़ 82 लाख हो चुकी है। यानी छात्र संख्या में बृद्धि लगभग 60 प्रतिशत की हुई है, किन्तु इसी अवधि में विश्व स्तर पर उच्च शिक्षा में हीने वाला सर्वजनिक छन्द सकल ग्राहक उत्पाद के 4.9 प्रतिशत से घटकर 4.8 प्रतिशत रह गया है।

विगत 17 वर्षों में मांग और सार्वजनिक खर्च की बढ़ती यह खाई ही उभरते शिक्षा बाजार का सबसे बड़ा

कारण है। बाजार को गिर्द दृष्टि से जीवन के किसी भी पक्ष का वच धाना सम्बन्धित होती है। इसीलिए मई 2000 में कनाड़ के बैंकर शहर में 'शिक्षा व्यापार में' का आयोजन किया गया था। विश्व व बाजार के पिछलागृहों अम्यानी और नियुक्ता होल्डर्स) सुनिश्चित करने का ही प्रतिफल है।

'दूसरा महत्वपूर्ण सबल यह है कि भारत के 'विकास पुरुष' 'हृदय मप्राट' 'यासस्वी' आदि करार दिये जाने वाले प्रधानमंत्री को इस प्रकार की परिप्रेरणा गरित करने और उसे शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे विषयों पर अनुशासन करने की खुली छूट देने की क्या गरज पड़ी थी? यह मसला सिर्फ शिक्षा जगत से नहीं बाल्कि हमारे संसदीय प्रजातंत्र की मूल भावना के प्रकटीकरण से भी जुड़ा हुआ है। जब संसद है, मौजिमण्डल है, मन्त्रालय है और उनसे सबबंद्ध सासदों की समीक्षा है तब उच्च शिक्षा स्तर पर छात्रों की संख्या 5 करोड़ 20 लाख थी, जिसकी तुलना में सन् 1997 में यह संख्या बढ़कर 8 करोड़ 82 लाख हो चुकी है। यानी छात्र संख्या में बृद्धि लगभग 60 प्रतिशत की हुई है, किन्तु इसी अवधि में विश्व स्तर पर उच्च शिक्षा में हीने वाला सर्वजनिक छन्द सकल ग्राहक उत्पाद के 4.9 प्रतिशत से घटकर 4.8 प्रतिशत रह गया है।

इस व्यवस्था के सभी तंत्र एक ही सुर और ताल में संलग्न है। विश्व वैकं अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और इन दोनों की चारण सुयुक्त ग्राहकों को कुछ संस्थाओं ने 'सुशासन' (गुड गवर्नेंस) के कुछ मानदण्ड तय कर रखे हैं जिन्हें हर उस ग्राहक को हासिल करना लाजिमी है, जो विश्व बाजार के सराना अमरीका से 'अति प्रिय ग्राहक' (मोस्ट फैवर्ड नेशन) का तमागा प्राप्त करने की ख्यालिश रखता है। इन मानदण्डों के मुख्य सूत्र हैं: आर्थिक फैसलों को राजनीतिक प्रक्रियाओं से परे रखना, कार्यपालिका का स्थायित्व सुनिश्चित करना, शामन को प्रक्रिया में विशेषज्ञों की भूमिका को जनप्रतिनिधियों के समतुल्य स्थापित करना और नियम प्रक्रिया में 'पत्तीदार' (स्टेकहोल्डर्स) की भागीदारी सुनिश्चित करना।

पहले दो मसलों पर यशस्वी प्रधानमंत्री की पीड़ा के प्रकटीकरण से तो हम सब बखूबी चाकिफ हैं। तीसरे मानदण्ड के लिए तो संवेधानिक चौर दरवाजे ही काफी रहे हैं जिनके जरिये विदेश मंत्री, विधि मंत्री, सूचना तकनीक मंत्री आदि कुर्सिनशी हैं। अभी हाल के वर्षों में पी.एम.ओ. का बढ़ता आकार, रुतना और कार्यदलों समितियों व परिषदों की बढ़ती भूमिका के जरिये विशेषज्ञों को जनप्रतिनिधियों के समकक्ष लाने के प्रयास भी जारी हैं। इन परिवर्तनों का वैधानिक आधार तैयार करने के काम में 'संविधान समीक्षा' के लिए बनाया गया आयोग शिद्दत से काम कर रहा है।

प्रधानमंत्री की उद्योग एवं व्यापार परिषद का गठन 'सुशासन' की चौथी शर्त 'पल्टीदारों' की भागीदारी सुनिश्चित करने का नायाब नमूना है और उसे ऐसे ही देखा समझा जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर भी सरकार उद्योग एवं व्यापार परिषद से सलाह कर रही है। अब शिक्षा यदि व्यापार और उद्योग है तब उसके सबसे बड़े पल्टीदार वही होंगे जो उसमें निवेश करेंगे, जबकि शिक्षक वर्गी हैसियत शिक्षा जगत के 'मजदूर' की होगी और छात्र व अधिभावक की हैसियत ग्राहक की। मजदूर और ग्राहक दोनों को ही हैसियत सत्ता समीकरण में क्या होती है यह सब जानते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इन दोनों समूहों से सलाह करने की उम्हरत नहीं समझी। प्रस्तुत रिपोर्ट को इन्हीं संदर्भों में ही देखा जाना चाहिए। जहाँ तक प्रस्तुत रिपोर्ट की सिफारिशों का सकाल है तो उनमें सबसे घातक और दूरगमी सिफारिश शिक्षा से क्रृष्ण बाजार को सुइड़ और विस्तृत करने की है। इससे शिक्षा के व्यापार में मुनाफे की तो गारंटी होगी, लेकिन आने वाले समय में जो बच्चे इस व्यवस्था से पढ़ेंगे, लिखेंगे, उनके लिए अपने मूल्यों, विचारों और इन्ड्राओं के अनुरूप काम करने की गुणाइश नहीं होगी। पढ़-लिखकर इसी विजारी व्यवस्था में खेप जाना उनकी नियति होगी, क्योंकि पढ़ाई के लिए लिया गया कर्ज जो लौटाना होगा ! यह एक नये प्रकार की दासता का सूत्रपात होगा। उस स्वातित्या संस्कृति का सर्वथा बिलोप हो जाएगा, जो किसी जनतात्रिक नागरिक समाज के लिए आवश्यक होती है।

राजनीति खत्म करने की राजनीति

आनंद प्रधान

"हमारे विश्वविद्यालय राजनीति के अखाड़े (हॉटबेड ऑफ पॉलिटिक्स) बन गये हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षक से राजनीता बन गये शिक्षक ही मुख्य रूप से उच्च शिक्षा के गिते स्तर के लिए जिमेदार हैं। विश्वविद्यालय यूनियनों को राजनीतिक कैरियर बनाने की पौथशाला के रूप में देखा जाता है। इस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए जल्ली है कि सभी राजनीतिक दलों के बीच यह समझदारी बने कि वे विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं से दूर रहेंगे। यह एक काल्पनिक विचार लगा सकता है लेकिन इस दिशा में यहते ही पहल की जानी चाहिए और शी बहुत जल्ली है कि विश्वविद्यालय परिसरों और शैक्षणिक संस्थाओं में हर तरह की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जाया।" -अंबानी-बिडला समिति को रिपोर्ट के अंश

अंबानी बिडला समिति द्वारा व्यक्त उपरोक्त विचार और सुझाव इस अर्थ में बहुत चौंकाते नहीं हैं क्योंकि वे पहली बार नहीं व्यक्त किये जा रहे हैं। इससे पहले भी ऐसे विचार शिक्षा पर गठित कई समितियों ने व्यक्त किये हैं या विभिन्न किस्म के सार्वजनिक मंचों और कारपोरेट भीड़िया में उहराये जाते रहे हैं। अलबत्ता इस बार जो फर्क है वह यह है कि अंबानी-बिडला समिति ने बिना किसी लागलपेट और शब्दजाल के बिल्कुल स्पष्ट और मुहफ़त अंदाज में विश्वविद्यालयों व शैक्षणिक परिसरों से राजनीति के सफाये की मांग उठायी है। जाहिर है कि यह सिर्फ संयोग नहीं है कि अंबानी बिडला समिति की यह मांग एक ऐसे समय में आयी है जब उच्च शिक्षा के निजीकरण//अभिजातीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ-साथ देशभर में परिसरों के सेन्ट्रीकरण का अभियान भी जोशर से जारी है। यह दृष्टिकोण देश में मौजूद हर समस्या के

लिए राजनीति, विशेषकर लोकतांत्रिक राजनीति व उनकी संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराने की गैरलोकतांत्रिक व निराभासतावादी सोच की ही एक और अधिक्यकृत है। राजनीति को गाली देना एक लोकप्रिय कौशल हो गया है। राजनीति को हर किस की बुराई का पर्याय बना दिया गया है। गोपा राजनीति न हो तो देश की हर समस्या खुद-ब-खुद हल हो जाएगी, लोगों की सभी मुश्किलों का अंत हो जाएगा और देश सुख-समृद्धि के भूमिकान की ओर बढ़ चलेगा।

दरअसल, राजनीति की ऐसी नकारात्मक और जुरी छवि पेश करने के पीछे भी एक राजनीति है। इस राजनीति का मकसद है लोकतांत्रिक राजनीति और उसकी तमाम संरथओं को बदनाम करके लोगों की नियाह में गिराना यानी उसका विश्वसनीयता व साख को खत्म कर देना। इससे लोकतांत्रिक राजनीति को खत्म करने में बहुत आसानी हो जाती है। लोकतांत्रिक राजनीति को सफाये का उद्देश्य है भूमिकाकरण, उदारीकरण और नियोकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के मार्ग को निष्कट्टक बनाना। स्पष्ट है कि परिसरों से राजनीति को बेदखल करने की मांग एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मानव सिर्फ परिसरों का ही नहीं है, उद्योगों व कारखानों से भी राजनीति के निष्कासन (श्रम कानूनों व ट्रेड यूनियन अधिकारों के ऊपर बढ़ते हमलों के जरिये) की मांग ही रही है। यही नहीं, पूरी अर्थनीति मांग किस सीमा तक पहुंच गयी है इसका अंदराजा वाजपेयी सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत वित्तीय उत्तराधिकृत व बजट प्रबंधन विभेदक से लागा जा सकता है। जो वस्तुतः अर्थनीति को राजनीति से स्वतंत्र करने का ही प्रस्ताव है। इस विधेयक के जरिये इस बात की पक्की व्यवस्था कर दी गयी है कि संसद में भी कम से कम आधिक मुद्रों पर कोई राजनीति न हो सको। इससे साफ है कि चीजें किस ओर जा रही हैं।

जब अंबानी-बिडला समिति के सुशांतों के अनुलेप उच्च शिक्षा के नियोकरण और बाजारीकरण के अधिकार को आगे बढ़ाया जाएगा तो परिसरों में उसका विरोध होगा। शिक्षक और छात्र इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और अपने हितों की रक्षा की कोशिश करेंगे। इस सम्भावित लड़ाई के संकेत साफ दिखायी पड़ रहे हैं। अंबानी-बिडला समिति को इसका पूर्वानुमान था, जूतिर झुग्गियों को बदनाम करने के लिए विश्वविद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा, विश्वविद्यालय

पूर्णियों को राजनीतिक कैरियर बनाने की पैंथशाला और शिक्षकों को राजनीता बताते हुए विश्वविद्यालय के गिरते स्तर के लिए जिम्मेदार ठहराने की कार्रियरा की है। ताकि परिसरों से उठने वाली विरोध की हर आवाज को इस तर्क के आधार पर आसानी से कुचला जा सके कि शिक्षक, विद्यार्थी और कर्मचारी हर समस्या खुद-ब-खुद हल हो जाएगी, लोगों की सभी मुश्किलों का अंत हो जाएगा और पाप हो।

परिसरों से राजनीति के सफाये की यह राजनीति सत्ता-प्रतिष्ठान को भी बहुत अनुकूल बैठ रही है। सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे शासक अधिजात्यों को इस बात की अशंका है कि आने वाले दिनों में भूमिकाकरण-उदारीकरण-नियोकरण की राजनीति के खिलाफ बढ़े। जन आंतरिक खड़े हो सकते हैं और इन आंदोलनों में परिसरों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने की नकालत का सत्ता प्रतिष्ठान का पूरा समर्थन प्राप्त है। वह अपने तरीकों से परिसरों को घेर रहा है। एक आंदोलन विश्वासिक गतिविधियों को ग्रोस्टाहित करने के नाम पर परिसरों में काला-पिञ्चा-एम. टीवी की आराजनीतिक संस्कृति को खबू बढ़ावा दिया जा रहा है और दूसरों आंदोलन विश्वासित का जमकर सैन्योकरण हो रहा है।

परिसरों के सैन्योकरण की परिषट्टा पर अलगा से विचार बहुत जहरी है। मिछले एक दशक में यह परिषट्टा अलग-अलग परिसरों में अलग-अलग रूपों में सामने आयी है लोकिन सब को मिलाकर देखें तो एक समूह तस्वीर बनती है। सैन्योकरण की यह प्रक्रिया परिसरों को बदनाम करते से शुरू हुई विश्वविद्यालयों की ऐसी छवि कारपोरेट मीडिया के जरिये पेश की गयी मानो परिसरों में हिस्सा, गुंडगर्दी, तोड़फोड़ के अलावा और कुछ नहीं होता है। छात्र संघों को अपराधियों के अड्डों के रूप में प्रचारित किया गया और छात्र राजनीति की कुछ ऐसी छवि बनायी गयी मानो परिसर की हर अर्थव्यवस्था के लिए वही जिम्मेदार हो। ऐसा नहीं है कि इस प्रचार में सचाई बिल्कुल नहीं थी लोकिन वह पूरी मानव नहीं थी। तथ्य यह है कि परिसरों में प्रशासन ने एक सुचित नीति के तहत एस तत्वों और उनकी गतिविधियों को ग्रोस्टाहित किया, उन्हें या संरक्षण दिया जिससे न सिर्फ विश्वविद्यालय के संसाधनों की लृपाट में मदत मिलती थी वल्कि उससे काले कारामे भी छुप जाते थे। इस तरह परिसरों की छात्र राजनीति या शिक्षक राजनीति, उसे खिलाऊ-पिलाऊ, भ्रष्ट बनाओ, बदनाम करो और दूध की गक्खी की तरह निकाल फेंको की नीति पर चल कर खत्म किया गया।

इसके बाद दूसरे चरण में परिसरों की अमली समस्या कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में पेश की गयी। इसके हल के लिए परिसरों में पुलिस के थाने खाले जाने लागे, पीएसों और दूसरे अधर्सेनिक बलों की स्थायी छावनियाँ बनायी गयीं, छात्र संघों को भाग कर दिया गया और विश्वविद्यालयों में आईएएस अफसरों और रिटायर्ड सैनिक अधिकारियों की कुलपति के रूप में नियुक्ति का चलन शुरू हुआ। जैसे मुम्बई विश्वविद्यालय परिसर में स्थायी रूप से धारा 144 थाप दी गयी, अलीगढ़ और जामिया विश्वविद्यालयों में छात्रसंघों को भाग कर क्रमशः एक आईएएस अधिकारी और सेना के रिटायर्ड लैप्टटनेट जनरल को कुलपति बनाया गया, वीएचयू में छात्र संघ को खत्म कर परिसर में पीएसी की स्थायी छावनी कायम कर दी गयी, बिहार में डेड दशक से छात्र संघों के चुनाव स्थगित हैं और शायद ही कोई विश्वविद्यालय परिसर बचा हो जहाँ ग्रॉक्टरियल बोर्ड की आड़ में सशस्त्र निजी सुरक्षा कमांडो दस्ते न खड़े कर दिये गये हों। कुलपति फौज-फाटे के बीच हते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन व आम छात्रों-शिक्षकों-कर्मचारियों के बीच कोई संवाद नहीं है। परिसरों में पुलिसिया आंतक का राज है। एक किस की अधोषित इमरजेंसी लगी हुई है।

सेन्योकरण की इसी प्रक्रिया की आली कड़ी है परिसरों में किसी भी क्रिस्म की राजनीतिक गतिविधि पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की सिफारिश जिसका तात्पर्य यह हुआ कि अधोषित इमरजेंसी को घोषित और औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाय। जाहिर है कि इस सिफारिश के निहितार्थ बहुत खतरनाक हैं। यह सीधे-सीधे लोकतंत्र की जड़ पर हमला है। राजनीतिक गतिविधि पर रोक लगाने की मांग सिर्फ विश्वविद्यालय परिसरों तक सीमित नहीं रहने वाली है। कल कों कारखानों में भी ऐसी ही मांग उठेगी और सार्वजनिक जीवन में राजनीति के प्रबंध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव होगा। उस दिन इस आपातकाल के खिलाफ बोलना राजनीति करना होगा जिसकी इजाजत देश में नहीं होगी।

सबल है कि क्या परिसरों में कानून बनाकर राजनीतिक गतिविधियों को रोक देने से ज्ञान-विज्ञान और शोध के क्षेत्र में हमारे विश्वविद्यालय नयी कंचाइयाँ छुट्टे लागें? उनका स्तर सुधर जाएगा? दुनिया में क्या ऐसा कोई उदाहरण है? कहने की जरूरत नहीं है कि अबानी-बिडला ऐसा एक भी उदाहरण नहीं दे सकते हैं। उल्टे आंतक और लानाशाही के माहौल में अच्छे-अच्छे विश्वविद्यालयों के पतन

अपहरण होने से बचाइए !

कपिल कुमार

यह तो सर्वविदित है कि उद्योगपति मुनाफा कमाने में कोई कसर नहीं छोड़ते तोकिन आज बिडला-अबानी रिपोर्ट ने देश की उच्च शिक्षा को भी इसी दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उच्च शिक्षा इन उद्योगपतियों के लिए एक बड़ा बाजार है जहां शिक्षा को एक उत्पाद के रूप में बेचकर ये मुनाफा कमाना चाहते हैं। इनके गास्टे में आज कोई रोड़ा आ रहा है तो वह है सरकारी शैक्षिक संस्थाएं, बिडला ने जो सिफारिशें अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री को भेजी हैं वे इतनी खतरानाक हैं कि यदि मान ली गयी तो उच्च शिक्षा के दबावजे के बल गरीब छात्रों के लिए ही नहीं बढ़ हो जाएं वरन् मध्यम श्रेणी के छात्र भी इससे हाथ धो बैठेंगे। यह एक ऐसी साजिश है जिसका द्वारा उच्च शिक्षा केवल सोने-चांदी के पालने में पले छात्रों को ही दी जाएगी और अमीर यारों का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति से पहले वहां एक कहावत थी कि 'सोनापति पालनों में पेता होते हैं' क्याकिं सामंत लोग अपने बच्चों के लिए ये पद खरीद लेते थे। कुछ ऐसी ही स्थिति आज के युग में अबानी और बिडला भारत में पैदा करना चाहते हैं। उनका मानना है कि सरकार को उच्च शिक्षा क्षेत्र से अपने को हटा लेना चाहिए। वास्तव में यह विचार 'निजीकरण' शब्द की आड़ में शिक्षा का वाणिज्यिकरण करना है जिससे कि उद्योगपति इस क्षेत्र में पेसा लागकर मुनाफा कमा सकें। रप्ट में कई अजीबोगरीब सिफारिशें की गयी हैं जैसे भारतीय शिक्षा प्रणाली का बाजारीकरण किया जाय, विश्वविद्यालयों के अनुदान समाप्त किये जाएं, जिस प्रकार से वित्तीय संस्थाओं का बाजार में मूल्यांकन किया जाता है उसी आधार पर शैक्षिक संस्थानों का भी किया जाय और जो संस्थान इसमें खरे नहीं उत्तरते उन्हें बढ़ किया जाय, छात्रों की फीस बढ़ा दी जाय आदि। इसी के साथ-साथ सूचना और प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय खोलने की बात बहुत ज़ोर देकर कही गयी है।

व्यक्तिगत तौर पर में निजीकरण का विरोधी नहीं हैं, क्यांकि भारत को उच्च शिक्षा प्रणाली का ढांचा पिछले 150 वर्षों में निजी प्रयासों द्वारा ही खड़ा किया गया और मजबूत बनाया गया। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और भारत के कोंने-कोंने में फैले न जाने कितने निजी कालेज इसके ज्वलत उदाहरण हैं। परं इन निजी प्रयासों के पीछे उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली कुछ खामियों के बावजूद एक सफल होना चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज कों नौकरशाही, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, नेता और यहां तक कि उद्योगों में काम करने वाले प्रबंधक इसी उच्च शिक्षा प्रणाली की दर्द है। वे नावर्ड या कैम्पस में पढ़कर नहीं आये हैं। सूचना प्रैद्योगिकों के क्षेत्र में भी आज जो सर्वोच्चता भारत ने हासिल की है वह इसी प्रणाली की दर्द है। हर क्षेत्र में महारथी बनाने के बावजूद यदि भारतीय मानस ने इस देश से बाहर नौकरी ढूँढ़ी तो उसके लिए भारतीय उद्योगपति उत्तरदानी हैं। हमारे देश के संपन्न और उत्कर्क प्रसिद्ध का उपयोग भारतीय उद्योगपति न तो औद्योगिक शोध के लिए कर पाया और न हो उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी दे पाया। अफसोस यह है कि आज हमारे इंजीनियरिंग कालेजों और कैंट्रीय विश्वविद्यालयों में 40 प्रतिशत शिक्षक पद रिक्त पड़े हुए हैं। कोई भी मेथावी छात्र एम.टेक, एम.सी.ए., एम.आइ.टी. इत्यादि को डिग्री उच्च श्रेणी में लेने के बाद शिक्षक नहीं बनना चाहता है। इसका कारण सिर्फ एक है कि जो तनखाह और सुविधाएं उसे शिक्षा के क्षेत्र से बाहर नौकरी करने पर मिलती हैं वह शिक्षा क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। यदि देश की शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाना है और भविष्य में आने वाले छात्रों को अच्छी सामाजिक विद्या का सामान्य उपलब्ध कराना होगा परंतु इसका जिक्र कहीं अच्छी और विडला रिपोर्ट में नहीं है। आज शिक्षा को बहुत सी दुकानें देश के चप्प-चप्प में खुल चुकी हैं और इनके मालिक खुलेआम शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं। बड़ा अच्छा होता यदि अबानी और बिडला अपनी सिफारिशें देने से पहले एक नज़र इन दुकानों पर भी डाल लेते। क्या इन दुकानों में योग्य शिक्षक हैं? कितने लाख रुपये ये 'दुकानें' प्रत्येक छात्र से लेती हैं और बदले में क्या पढ़ती हैं? कितने विद्यार्थी अपनी

शिक्षा यहां बीच में ही छोड़ जाते हैं और कितने विद्यार्थियों के साथ यहां भ्रंगाधुरी की जाती है? येर, इस सबसे बिडला-अंबानी का क्या बास्ता? उनके जिए तो सारी त्रुटियां विश्वविद्यालयों में ही हैं।

यह एक यथार्थ है कि भारत के उद्योगपतियों ने सरकारी संरक्षण के तहत पनपना सीखा और अपना एकाधिकार स्थापित किया। ये उद्योगपति तो अपने उत्तादों के क्षेत्र में शोध और विकास तक नहीं कर पाये। सबाल यह है कि भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपने दरवाजे इनके लिए कब बंद किये थे? किंतु उद्योगपतियों ने शिक्षा के विकास के लिए अनुदान दिये या शोध के लिए संगीत, सांस्कृतिक विकास आदि उच्च शिक्षा से अलग नहीं किये जा सकते। जिसका कार्य केवल कलाओं को अनुदान देने तक सीमित कर दिया जाय। उसका कार्य उसके लिए अनुदान को किसी भी समाज में एक अलग आयकर छूट से। उनका बास्ता है सिर्फ मुनाफा कमाने से और अगर ऐसा नहीं है तो क्या वह बिना मुनाफा कमाये या बिना वितीय लाभ उठाये निजी विश्वविद्यालय चलाएंगे?

संपन्न पाठ्यालय देशों से शिक्षा के प्रारूप और ढाँचों को उठाकर भारत के परिवेश में थापना इन उद्योगपतियों के लिए एक फैशन बन गया है। इन संपन्न देशों की प्रबंध तकनीक, शोध नीति आदि को अपने उद्योगों में लागू करते हुए तो ये करतारत हैं, लेकिन वास्तविकता का जायजा लिये बिना उन प्रारूपों के केवल चंद पहलुओं और कालेजों के मूल्यांकन को इनकी बात मान ली जाय तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत के 95 प्रतिशत विश्वविद्यालय और कालेज बंद हो जाएंगे। आवश्यकता इन संस्थाओं का मूल्यांकन कर उहें बंद करने की नहीं है वल्किं कमज़ोर संस्थाओं को सरकारी मदद से और मजबूत बनाने की है। वास्तव में शिक्षा संस्थाओं के मूल्यांकन का विषय अपने में एक अलग बहस का मुद्दा है।

जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में 200 वर्ष पूर्व अपनी शिक्षा प्रणाली से यह प्रयास किया था कि उनके लिए बाबू उपलब्ध हो सकें, उसी प्रकार अंबानी और बिडला अब एक ग्रंथि शिक्षा प्रणाली लाना चाहते हैं, जो उनके लिए और उनके केवल उनके निजी विद्यालयों में लाखों रुपये खर्च कर पढ़े-लिखे अपनीं के बेटे। छत्रधारी बहुगण्य कपणियों के लिए सस्ते मजदूर और बाबू दे सकें। मैनेजर बनेंगे किसी भी विकासशील समाज में उच्च शिक्षा का उद्देश्य मात्र बाजार की मांग को

मान लिया गया तो समाज में न तो विचार ज़मेंगे, न तर्क की कोई जगह होगी और न ही विचारधारा का कोई स्थान रहेगा। समस्त शिक्षा प्रणाली और समाज केवल बाजार का गुलाम बनकर रह जाएगा और यह हमारी संस्कृति और परंगागत धरोहर पर एक आघात होगा। मेरी दृष्टि में बाजार उच्च शिक्षा का निर्भरक नहीं हो सकता। उद्योगपतियों की जलूरतों को पूरा करने के विरुद्ध उच्च शिक्षा के समाज में बहुत से दायित्व और कार्य हैं। सामाजिक मूल्यों को जीवित रखना, ज्ञान का विकास, मानवाधिकार, स्त्री अधिकारों की रक्षा, दर्शन, कलाएं, बिडला-अंबानी यह चाहते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी पंगु बना संगीत, सांस्कृतिक विकास आदि उच्च शिक्षा से अलग नहीं किये जा सकते। जाय। मानविकी और सामाजिक विज्ञानों को किसी भी समाज में एक अलग अहिमयत है और मुझे यह विश्वास है कि अंबानी-बिडला जैसे व्यक्ति चाहे कितने भी प्रहर क्यों न कर लें, देश को यही विषय जीवित रखेंगे न कि भाव रहित सूचना और प्रौद्योगिकी। देखता तो यह है कि जो टिप्पणियां अंबानी-बिडला ने विश्वविद्यालय में राजनीति को भूमिका को लेकर की हैं उन पर हमारे राजनीतिक क्षय करते हैं। बिडला-अंबानी यह भूल गये हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई में विश्वविद्यालयों ने एक अहम भूमिका निभायी थी। भारतीय लोकतंत्र को सशक्त करने में विश्वविद्यालयों ने एक अहम भूमिका निभाया था। आज के कई इमानदार नेता भाजपा आंदोलन और भाजपा राजनीति की देन हैं। बिडला-अंबानी को विश्वविद्यालयों में राजनीति पनपने से तो बहुत चिढ़ है एवं जो अपराधिकरण समाज और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है उस पर वे पूणितया शांत हैं। शायद इसलिए कि कोई अपराधी पिस्तौल दिखा कर लूटता है और कोई टैक्स चोरी करके देश को लूटता है। कोई अपराधी अपहरण करके फिरते मानता है तो बिडला-अंबानी रिपोर्ट पूरे देश की शिक्षा प्रणाली का अपहरण कर आम जनता से फिरती मानते का एक ऐसा आपराधिक घटयंत्र है जिसका जबाब देश की जनता को देना होगा और वही इसे विभाल करेंगी।

दाखिला से वंचित दलित

चन्द्रभान प्रसाद

उच्च शिक्षा के निजीकरण का अर्थ है दलितों को उच्च शिक्षा से बचात करना। क्योंकि पूर्व में हमने देखा है कि किस तरह दलित जातियों के बच्चों के स्कूलों में जने के कारण सर्वां जातियाँ इतनी कुद्द हो गयी थीं कि उन्होंने दलितों और अस्मृत्यु जातियों के गांवों को आग के हवाले कर दिया था। सुप्रसिद्ध 'बुद्धस डिस्ट्रिच' (1854) को भारत में जन-शिक्षा का 'मौनाकर्ता' कहा जाता है। इसके आने के बाद ब्रिटिश हुक्मत को जन शिक्षा लापू करने में काफ़ी मुसीबत उठानी पड़ी थी। अस्मृत्यों के गांव हुक्मत को जन शिक्षा लापू करने में काफ़ी मुसीबत उठानी पड़ी थी। अस्मृत्यों के गांव जला दिये गये थे। बांगल से यावद तक सरकार ने सख्ती का रख अपनाया तो सख्ती जातियों ने अपने बच्चों को स्कूलों से वापस बुलाना शुरू कर दिया था। हास्कर सरकार ने देश भर में अस्मृत्यों के लिए अलग स्कूल खोले थे। बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बांग्ल प्रेसीडेंसी की 1950-52 की रिपोर्ट में कहा गया था—“इसमें सदैह नहीं, यदि अस्मृत्यों के भीतर एक ऐसा वर्ग बन जाता है जो प्राध्यापकों से शिक्षा लेकर न्यायाधीश, अन्यगत आदि पदों पर बैठना चाहेगा तो उनको आकांक्षा को कौन रोक पाएगा।” रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि यदि ब्रिटिश हुक्मत अस्मृत्यु वर्ग को उच्च पदों से बंदित करती है तो अंग्रेज सहृदय लोग इसे सरकार की गैर-उदारतादिता की है कहेंगे। यह रिपोर्ट तत्कालीन ब्रिटिश हुक्मत की इस उलझन को प्रकट करती है कि अंग्रेज अस्मृत्यों को शिक्षा तो दिलाना चाहते थे, लेकिन सबंध वां इसका प्रतिरोध करेगा इस बात से बंदित रहती है। आज उच्च शिक्षा के निजीकरण की कवायद हो रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2000 में कुल 20.59 करोड़ दलित हैं जिनमें से मात्र 2018 ही पी.एच.डी. और 76928 स्नातकोत्तर कक्षाओं में हैं यानी बगैर निजीकरण के भी ते उच्च शिक्षा से बाहर हैं और निजीकरण के बाद तो हालात और बदतर हो जाएं। शिक्षा का अद्वे निजीकरण पहले से ही है। भारत में शिक्षण संस्थाएं मुख्यतः तीन श्रेणियों में आती हैं—पूर्ण सरकारी, सरकारी किन्तु स्वायत्त और निजी। पूर्ण सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दलितों को काफ़ी राहत है क्योंकि यहाँ सर्विधान को पूरी तरह लापू करना पड़ता है चाहे मानला छांतों के प्रवेश का हो या फिर अध्यापकों की नियुक्ति का। लोकन स्वायत्त संस्थाएं जिनमें मुख्यतः कॉलेज एवं विश्वविद्यालय आते हैं वहाँ दलितों की दरशा बदतर है। यद्यपि इन संस्थाओं का गणा एवं शिक्षा लापू करना चाहते, वे दलितों को बचाते हैं कि सर्विधान को नहीं पाना है। बहस इस बात पर कोई विवर होनी चाहिए कि दलितों को सर्विधान में निर्धारित उनका तक दलितों जब संस्थाओं का निजीकरण नहीं हुआ था, तब भी वे संस्थाएं निजीकरण जैसे ही अन्य दलितों की हो गई थी। संस्था सर्विधान से ऊपर नहीं है। इसलिए गणना हरे जगह

सर्विधान को आधा-अधूरा लापू किया जाता है। मौरिट के नाम पर दलितों को दाखिला के रूप में नियुक्त नहीं निलती। इस तरह इनमें से अधिकांश कॉलेज-विश्वविद्यालय निजी संस्थाओं से भी बदतर हैं। इन संस्थाओं का सारा खुन सरकार उठाती है पर इनका आचरण निजी संस्थाओं जैसा है। ये दलितों को बचाते हैं तो करते ही हैं उन पर 'गैर-मेरिटोरियस' होने का उप्पा भी लगाया जाता है।

तो सरी श्रेणी में इन्हिंसा मौड़ियम ने पर्विक रक्कूल या पार्मिक स्पार्टनों द्वारा चलाये जा रहे शिक्षालय आते हैं। अंग्रेज माध्यम के इन स्कूलों को इस अधेर में मवसं ज्यादा खतरानाक कहा सकते हैं कि ये देश के प्रथु वर्ग के बच्चों को पढ़ाते हैं जो उच्च पदों पर जाते हैं, एकेंड्रिम संस्थाओं में बढ़े होने के बावजूद भी दलित बहिष्कार के प्रयत्न पर ये गरजनीतिक विचारधाराओं में बढ़े होने के बावजूद भी दलित बहिष्कार के प्रयत्न पर ये लोग एकजुट हो जाते हैं। क्या किसी वामपंथी या दक्षिणपंथी या सामाजिक न्यायवादी संगठन ने राष्ट्रीय स्तर पर यह मां उठायी कि अंग्रेज माध्यम के स्कूलों में सर्विधान संस्थान चाहिए? या कभी संसद में विषय ने इस मरते पर बहिष्कार किया है? सबाल निजीकरण या सरकारीकरण का नहीं है। देश की पुख्त उच्चस्तरीय विद्यालय लोग एकजुट हो जाते हैं। क्या किसी वामपंथी या दक्षिणपंथी या सामाजिक न्यायवादी संस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर यह मां उठायी कि अंग्रेज माध्यम के स्कूलों में सर्विधान संस्थान चाहिए? या कहीं संसद में विषय ने इस मरते पर बहिष्कार किया है? सरकारी है। सर्विधान को हर जाह लापू किया जाना चाहिए, चाहे सरकारी संस्थान हो या गोर संस्थाएं मूलतः निजी हाथों में हैं जहाँ प्रवेश या नियुक्ति के लिए सर्वांगीन चाहिए। या गोर सरकारी दलितों को कम से कम उनका एक-चौथाई हिस्सा मिले। टीक वेस ही जैस अमरीका में होता है। भारत में दलितों की बच्चों को कोई तुलना अमर किसी समाज में हो सकती है तो वह अमरीकी और दक्षिण अफ्रीकी सामाज है जहाँ कालों को दलितों की तरह शिक्षण संस्थाओं से दूर रखा गया था। 1960 में वहाँ कालों और गांधी व्यापक स्तर पर हिंसा भड़क उठी थी। अमरीकी समाज संकट के दोष में फ़स गया था। फिर शांति की आकाश प्रबल हुई। गोर समाज ने समर्पित और संस्थाओं पर अपने कब्जे को लेकर गोर करना शुरू किया। पारिणाम सकारात्मक निकला। कानून रट इंडियां और हिस्पैनिक्स की शिक्षण संस्थानों में भागीदारी मंजूर की गयी।

भारत में जो लोग सर्विधान को लापू करवाने में आगे नहीं आना चाहते, वे 'वौरेपन' की मानसिकता पाते हुए हैं कि सर्विधान को नहीं पाना है। बहस इस बात पर कोई विवर होनी चाहिए कि दलितों को सर्विधान में निर्धारित उनका तक दलितों जब संस्थाओं का निजीकरण नहीं हुआ था, तब भी वे संस्थाएं निजीकरण जैसे ही अन्य दलितों की हो गई थी। संस्था सर्विधान से ऊपर नहीं है। इसलिए गणना हरे जगह

गोर चाहिए।

